22 दिसम्बर, 2014

INDIAN COUNCIL OF
WORLD AFFAIRS
VIEWPOINT

दक्षेस/सार्क: क्षेत्रवाद हेतु नए विकल्पों की तलाश की घड़ी

डॉ. अमित कुमार[*]

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) का 18 वाँ शिखर सम्मेलन, जो 26-27 नवम्बर के दौरान नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था, ऊर्जा सहयोग पर अंतिम समय में हुए सौदे के सिवाय कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया। हालांकि, 18वें शिखर सम्मेलन का विषय "शांति और संपन्नता हेतु गहन समन्वय" था, लेकिन विडंबना यह है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) के सदस्य सड़क और रेल संपर्क जैसे ज्यादा जरूरी करारों पर हस्ताक्षर करने में विफल रहे, जिसका कारण दक्षेस/सार्क में पाकिस्तान का 'अवरोधवादी' दृष्टिकोण था। तथापि, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दक्षेस/सार्क की वह गतिशीलता, जो छह महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए दक्षेस/सार्क के नेताओं को निमंत्रण देकर उत्पन्न की गई थी, फीकी पड़ चुकी है या भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में अपनी रुचि खो दी है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के पहले भाषण ने निकट भविष्य में दक्षेस/सार्क सदस्य देशों के बीच सहयोग की कुछ आशा जगाई है। उनके भाषण से यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली दक्षिण एशियाई आर्थिक ब्लॉक के भीतर अत्यंत आवश्यक अंतरा-क्षेत्रीय (इंट्रा-रीजनल) समन्वय (कार्य को) आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हो सकता है, आने वाले वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में सहयोग का तरीका बदल जाए। प्रधानमंत्री मोदी का विकास का पिछला रिकॉर्ड; दक्षिण एशिया के विकास के प्रति उनकी चिन्ता और भारत के विकास को दक्षिण एशिया के विकास से जोड़ने की प्रवृत्ति; दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में सकारात्मक एकपक्षीयता की कार्यनीति; और सब से बढ़कर, वायदा करने तथा उसे पूरा करने के बीच के अंतर को कम करने के हाल के उनके प्रयास दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन(दक्षेस/सार्क) के नेताओं को भारतीय नेतृत्व पर भरोसा करने का यकीन दिला रहे हैं। भारत-

नेपाल विद्युत व्यापार करार पर वायदानुसार 45 दिनों की समय सीमा के भीतर सहमति कायम होना बहुत हद तक नेपाल में भारत की छवि में सुधार ही करेगा।

विश्व में आर्थिक दृष्टि से सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) भारत-पाकिस्तान मतभेदों की छाया से बाहर निकलने का इन्तजार कर रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) के देशों के बीच आपसी अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार दक्षेस/सार्क के विश्वव्यापी व्यापार का लगभग पांच प्रतिशत है, जो कुछ अन्य क्षेत्रीय संगठनों/ब्लॉकों, जैसेकि आसियान (लगभग 25 प्रतिशत) और यूरोपीय संघ (लगभग 60 प्रतिशत) की तुलना में एक निराशाजनक आंकड़ा है। यह दिलचस्प है कि वर्ष 1947 में हुए भारत के विभाजन के ठीक पहले, इस क्षेत्र में अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार लगभग 20 प्रतिशत था, जो नई राजनीतिक सीमाओं के उभरने के साथ ही अचानक बिखर गया।

दक्षिण एशिया में अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार कम रहने के प्रमुख कारणों में से एक कमजोर संपर्क/आवागमन व्यवस्था रही है। यदि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) अन्तर-क्षेत्रीय के साथ-साथ अंतरा-क्षेत्रीय संपर्क/व्यापार को पुनर्जीवित करना है तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए। अंतरा-क्षेत्रीय व्यापार की गति बढ़ाने और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यापार की लागत में कमी लाने के लिए भी, सड़क, रेल, समुद्री तथा हवाई नेटवर्कों को बेहतर बनाना अनिवार्य है। दक्षिण एशिया में (परस्पर) संपर्क/आवागमन हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान, इस क्षेत्र में निर्बाध संपर्क/अवागमन (व्यवस्था) की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचा/सुविधाएं हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसपर सबसे ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। जब मैंने सड़क (मार्ग) से काठमांडू आने के बारे में सोचा तो इसने भारत में कई अधिकारियों को बेचैन कर दिया।"

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में पाकिस्तान के अवरोधक दृष्टिकोण के कारण मोहभंग होने के बाद अब भारत दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने के नए विकल्प की तलाश में है। सी. राजा मोहन द्वारा सुझाए तथा दिए गए तीन विकल्प – उप क्षेत्रीय सहयोग, सीमापार क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क और एकपक्षीय कार्रवाई - दक्षिण एशिया में सामाजिक-आर्थिक सहयोग बढ़ाने का व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। भारत ने पहले ही एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) उपग्रह, रोगियों तथा (उनके) परिचर के लिए तत्काल चिकित्सा वीजा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) व्यापार यात्री कार्ड, और बुनियादी ढ़ांचे/सुविधा संबंधी परियोजनाओं के लिए विशेष प्रयोजन सुविधा प्रारंभ करने का वायदा किया है। यदि दक्षिण एशियाई ऊर्जा ग्रिड को विकसित करने में कठिनाइयां आती हैं, तो भारत को पूर्वी और दक्षिणी ऊर्जा ग्रिड को विकसित करने का

प्रयास करना चाहिए। भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बीच उप-क्षेत्रीय स्तर पर जल-विद्युत उत्पादन और व्यापार की अत्यधिक संभावनाएं हैं। भारत, बांग्लादेश तथा म्यांमार (दक्षेस/सार्क में पर्यवेक्षक) ऊर्जा (गैस) सहयोग में भी भागीदार बन सकते हैं। यदि नई दिल्ली पश्चिमी क्षेत्र में भी उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है तो इसे चाबहार परियोजना में तेजी लानी होगी जो भारत को 'चारों दिशा में भूमि से घिरे' अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने का एक व्यवहार्य/संभावित मार्ग है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) के भीतर उप-क्षेत्रीय सहयोग तथा सीमाक्षेत्र-पार आर्थिक ब्लॉकों के साथ संपर्क/व्यापार की यह योजना किसी शून्य से बाहर नहीं आ रही है; वास्तव में, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) घोषणापत्र/चार्टर में ही नीहित है। उपक्षेत्रवाद के विचार को बढ़ावा देने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) घोषणापत्र के अनुच्छेद VII में उल्लेख है, "स्थायी समिति परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सदस्य राष्ट्रों से बनी कार्य समितियों का गठन कर सकती है, जिसमें दो से अधिक (सदस्य राष्ट्र) शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभी सदस्य राष्ट्र शामिल नहीं हो सकते।" इसके अलावा, घोषणापत्र का अनुच्छेद 1 (ज) समान लक्ष्यों तथा उद्देश्यों वाले सीमापार-क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग करने की योजना का समर्थन करता है।

इस शिखर सम्मेलन को चीन की हैसियत एक पर्यवेक्षक से बदलकर वार्ता सहयोगी की करने के लिए जबरदस्त पैरवी करने के पाकिस्तान के प्रयासों के लिए भी याद किया जाएगा। नेपाल के वर्तमान मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों सहित वहां के राजनेताओं ने भी चीन की सदस्यता के पक्ष में अपनी आवाज उठायी। हालांकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में चीन की हैसियत बढ़ाने का प्रयास भारत द्वारा 'नाकाम' कर दिया गया, लेकिन यह दक्षेस/सार्क में चीन की सदस्यता पर भारत की 'दुविधा' का अंत नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) में चीन की पूर्ण सदस्यता का मुद्दा अभी भी वाद-विवाद का विषय है। तथापि, चीन दक्षेस/सार्क में शामिल हो या न हो, नई दिल्ली के पास अपने पड़ोसी देशों से आर्थिक संबंध विकसित करने और उन्हें अपने साथ सामाजिक-आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं है। साथ ही, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) को 'एइट ऑर नॉट फार्मूला' से परे भी विचार करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की खोज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए ।

**डॉ० अमित कुमार विश्व मामलों की भारतीय परिषद में अनुसंधान अध्येता हैं।*